ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **28 June, 2021**

Prof. Gourav Vallabh, Spokesperson, AICC and Shri Aman Panwar, National Media Panelist, AICC addressed the media via video conferencing today.

प्रो. गौरव वल्लभ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दो-तीन चीजें पहले समझेंगे और फिर हम हमारी प्रेस वार्ता के मुद्दे पर आएंगे। पिछले 16 माह में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो पेंडेमिक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिट नहीं हुआ और उसका प्रमाण ये है कि पिछले 16 महीनों में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। लगभग 4 लाख लोगों ने अपनी जान कोरोना से गंवाई। ये सरकारी आंकड़े हैं और जो डेटा मैनेजमेंट का आंकड़ा है, जो तरह-तरह के समाचार पत्रों में पब्लिश हो रहे हैं, देश-विदेश में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 3 करोड़ लोग कोविड पॉजिटिव हुए, 3 करोड़ से ज्यादा अभी तक और लगभग 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई कोरोना की बीमारी के कारण। 2020 में 3 करोड़ 20 लाख लोग मध्यम आय वर्ग से निम्न आय वर्ग में चले गए। साढ़े सात करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। 2020 में 97 प्रतिशत हिंदुस्तान के लोगों की आय में कमी हुई। ये सारे आंकड़े हैं, ये सीएमआईई का आंकड़ा है, जो माइग्रेशन टू मिडिल इंकम ग्रूप टू लोअर इंकम ग्रुप का रिसर्च का आंकड़ा है और जो लाइफ और लाइवलीहुड की बात करते थे कि हम जान है, अभी जहान पर करेंगे, फिर जान पर करेंगे, कभी जान पर करेंगे, फिर जहान बचाएंगे, वो दोनों जगह मिजरेबली सरकार फेल है। इन दोनों आकड़ों से सच्चाई निकल कर बाहर आ रही है।

अब कोविड 19 में आगे एक और घटना घटित होती है कि हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है। जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति की इस तरह के हादसे में मृत्यु हो जाती है, डिजास्टर में उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो एक निश्चित राशि, कंपनसेशन के रुप में दी जाती है। पर जो एफिडेविट, शपथ पत्र 19 जून, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बाबत फाइल किया गया, उसमें सरकार ने ऐसी-ऐसी बातें लिखी, जिसको पढ़कर लगता है कि लोकतांत्रिक देशों की सरकार ऐसा कदापि नहीं लिख सकती और अगर लोकतांत्रिक देश की सरकार ऐसा लिखती है, तो उसे एक क्षण भी शासन व्यवस्था में रहने का अधिकार नहीं। उनको पढ़कर लगता है कि जो सरकारें ऐसा लिख रही है, उसके हृदय में उनके देश के लोगों के लिए एक प्रतिशत भी सहानुभूति नहीं। ऐसा लगता है कि सरकार एक कठोर तरह का दंड देश के लोगों को देना चाहती है और मैं कुछ

वाक्य उस एफिडेविट में से निकाल रहा हूं, जो आपको सारे एफिडेविट की प्रति, जो वाक्य में आपको कोट कर रहा हूं, वो एक-एक आपके सामने रखूंगा।

पहला, सरकार ने कहा कि डिजास्टर दो तरह के होते हैं। ये देखिए, ज्ञान देखिए सरकार का। अनआईडेंटिफाइड डिजास्टर, आईडेंटिफाइड डिजास्टर, मतलब जिसका पहले से अंदेशा हो और जिसका पहले से अंदेशा नहीं हो। इस तरह की दो आपदाएं होती हैं। जिसका आईडेंटिफाइड डिजास्टर है, उसको हम डिजास्टर बोलेंगे, उसका कंपनसेशन देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और जिसका कोई अंदेशा ना हो, उसको आपदा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, ताकि हमें जिन लोगों ने अपना शरीर त्याग दिया, उनके परिवार वालों को मुआवजा ना देना पड़े। ये हमारे देश की सरकार ने डिजास्टर को, आपदा को दो भागों में विभाजित करके बताया। फिर बोला गया उस शपथ पत्र में, 19 जून का जो एफिडेविट है, उसी के अंदर से मैं बात कर रहा हूं। उसमें कहा गया कि हमें इस बात का खेद है कि लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सरकार लिख रही है। आगे लिखती है सरकार उसी शपथ पत्र में कि हमें पता है कि लोगों को मदद की आवश्यकता है, पर एक्सग्रेशिया एक रकम मृत व्यक्ति के परिवार को कोई एक रकम देने से उस मदद से कोई फायदा नहीं होगा। हमें पता है कि इस तरह की मदद की आवश्यकता है, पर हम इस तरह की मदद नहीं दे सकते हैं। We cannot provide ex-gratia payment. फिर एक और बात लिखी गई कि इस तरह की मदद देना एक नैरो और पैडेंडिक अप्रोच है, मतलब संकीर्ण भावना है। कोई व्यक्ति अगर अपनी जान गंवाता है इस पैंडेमिक में, आपदा में, इस आपदा में अगर जान गंवा रहा है, तो उसके परिवार वालों को मुआवजा देना सरकार की संकीर्ण अप्रोच लगती है। पैडेंडिक का मतलब है – नियमों और विवरणों पर अत्याधिक ध्यान देने वाली अप्रोच है। ये सरकार ने शपथ पत्र में लिखा है।

फिर आगे लिखते हैं कि नागरिकों को ऐसा कोई लीगल अधिकार नहीं है कि वो सरकार से एक्सग्रेशिया पेमेंट की मांग कर सकें। क्यों नहीं है, हम पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं है और उसका कारण देना चाहिए?

पिछले एक साल में 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए लोगों ने अपने पीएफ खाते से निकाला। पीएफ खाता क्यों रखता है कोई व्यक्ति – कोई मध्यम आय वर्गीय सैलरीड क्लास वर्किंग पर्सन, ऑर्गनाइज्ड या अन ऑर्गनाइज्ड क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति पीएफ खाता क्यों रखता है, ताकि बुढापे में वो सम्मान की जिंदगी जी सके। पर पिछले एक साल से सवा लाख करोड़ रुपए पीएफ खाते से निकला 1 अप्रैल, 2020 से लेकर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इन खातों से निकला है।

हम मांग करते हैं इस बाबत कि जब एक साल में 2020-21 में लगभग 4 लाख करोड़ प्रिसाइजली बोलूं तो 3 लाख 90 हजार करोड़, पेट्रोल-डीजल के एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने कलेक्ट कर लिया। क्या हम, हमारे जो लोग, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, इस कोरोना महामारी में। जो कोरोना की जंग कोरोना से लड़ते-लड़ते हार गए। वो लोग, जिनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली,

जिसके कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, वो लोग जिनको समय पर इंजेक्शन और दवाई नहीं मिली, इस कारण से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, क्या हम इन 4 लाख करोड़ की जो लूट है और मैं इसको लूट बोलता हूं, इस आपदा में 2020-21 वर्ष में 4 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट हुआ। इस 4 लाख करोड़ की लूट में से मात्र 10 प्रतिशत अर्थात 40 हजार करोड़ इन 4 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए देकर नहीं की जा सकती? क्यों नहीं की जा सकती और जो सरकार, जिनका कोरोना में स्वर्गवास हुआ, उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए नहीं दे सकती, उस सरकार को एक क्षण के लिए भी शासन में रहने का अधिकार नहीं और हम तो 10 प्रतिशत ही मांग रहे हैं, जो आपने लूटा है 4 लाख करोड़ का पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बड़ा-बढ़ा कर, निरंतर, जब से सरकार बनी 2014 से, तब से बढ़ाकर। पिछले एक साल में आपने 4 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और 4 लाख लोगों का स्वर्गवास हुआ।

हम मांग करते है कि आप 10 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिवार को तुरंत प्रभाव से दो, जिससे कि ये जो आपने पेट्रोल और डीजल से इकट्ठा किया, उसका मात्र हम 10 प्रतिशत की मांग करते हैं।

हम मांग करते हैं कि इस तरह का ये आइडेंटिफाइड डिजास्टर है, मतलब पूरा, ये पूरी देखी-समझी आपदा है, ये बिना देखी आपदा है, इस तरह का भेदभाव और इस तरह से लोगों की भावनाओं से ना खेंले।

हम मांग करते हैं कि आपने जिस तरह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में यू टर्न लिया, आईडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड डिजास्टर का भेद करके, इस भेद को समाप्त करें। हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए तुरंत प्रभाव से मुआवजे के रुप में दिया जाए और ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, मात्र 10 प्रतिशत है, सिर्फ पेट्रोल और डीजल से लूटा गया है पिछले एक साल में, उसका मात्र 10 प्रतिशत है।

हम मांग करते हैं कि जो बार-बार राहुल गांधी जी ने भी अपने प्रेस वार्ता करके आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखी थी। उसमें एक महत्वपूर्ण आधार जो उन्होंने रखा था, वो रखा था कोविड कंपनसेशन फंड का। हम मांग करते हैं कि ये कोविड कंपनसेशन फंड तुरंत एक कोविड कंपनसेशन फंड का निर्माण किया जाए और इस फंड से 10 लाख रुपए हर मृतक के परिवार को तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर किया जाए। ये हम कोई उन पर अहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है उस लोगों के प्रति। ये हमारा दायित्व है उन लोगों के प्रति, क्योंकि इन 4 लाख लोगों में से कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने सेवा करते-करते, फ्रंट लाइन वारियर्स ऐसे हैं, जिन्होंने देश के लोगों की सेवा करते-करते अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना कोई अहसान नहीं है। ये सरकार का दायित्व है और जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा शपथ पत्र देती है कि ये नेरो अप्रोच है, ये पैडेंडिक अप्रोच है, ये सही अप्रोच नहीं है, ये अन आइडेंटिफाइड डिजास्टर है। हम सिर्फ आईडेंटिफाइड डिजास्टर का मुआवजा देते हैं। जो सरकार इस तरह की तर्कहीन बात करती है

और मैं कहूंगा, जिस सरकार में इतनी भी एंपेथी नहीं है अपने नागरिकों के प्रति, उस सरकार को एक क्षण के लिए भी शासन व्यवस्था में रहने का अधिकार नहीं है।

Prof. Gourav Vallabh said- Modi Government Has Failed the People, Has No Right to Rule

Modi Government has Insulted the Deceased and Weakened our fight Against Covid

Our nation has been fighting the deadly Corona virus for the last 16 months now. So far, close to 4 lakh people have lost their lives and more than 3 crore people have been infected with this deadly virus. India's middle class shrunk by 3.2 Cr & 7.5 Cr people were pushed below poverty line in 2020. As per CMIE, close to 97% of Indians became poorer during the last year. It is clear that both Life and Livelihood have suffered badly. But the big issue is that the BJP government has left the people alone in this fight and doesn't seem to be bothered at all.

COVID-19 checks all boxes of a disaster. The government however seems to be hellbent in proving that this is not a disaster. In March 2020, the Ministry of Home Affairs decided to treat Covid-19 as a "notified disaster". However, when the demand for compensation was made in Public Domain, the Modi Government took a U-Turn in the honorable Supreme Court by saying that it cannot be called a Disaster and is at best a Pandemic. The affidavit dated 19.06.2021 filed by the government is a blow to our fight against COVID-19.

The government in its lame defense suggests a number of different arguments:

- According to the government, an unidentified disaster is not akin to an identified disaster. In the "disaster" originally contemplated, is a one-time occurrence or the same occurs repeatedly for few times like floods, earthquake, cyclone, different kinds of "interim measures of relief" are to be provided
- While the government expresses regret and sadness to the families of the deceased, this is all they can offer (Page 48/ Para 51 of the affidavit)
- Although the Government is fully conscious of the need to provide them the necessary help and support, the Government cannot provide such support through ex-gratia assistance for those who have died (Page 49 of the affidavit)
- The government calls support through compensation as a rather pedantic and narrow approach
- Citizens have no Legal Right to claim 'Ex-Gratia' compensation, say Modi Government in Supreme Court (Page 52/ Para 55)

The government collected close to Rs 3.90 Lakh crore only as Excise Duty collections in 2020-21. The government's argument there too is that this excessive collection is being directed towards the relief measures for the common man. This is contrary to the ground realities. Close to Rs 1.25 Lakh Crore has been withdrawn by people from their PF accounts since 1st April 2020. This is because the government failed to provide support of any kind to the middle class and low-income groups.

MHA Letter No. 32-7/2014-NDM-I Dated 8th April 2015 stated that Rs.4.00 lakh per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority. This was for the period 2015-2020. COVID-19 struck in this period. We will not allow the Government to unconstitutionally ignore this notification and all those who lost their lives amidst the Covid-19 pandemic must be granted the Rs. 4 lakh compensation under the Disaster Management Act.

We have three specific questions for the government:

1. When nations such as the USA have classified COVID-19 under natural disasters and all terms of Natural Disaster apply on COVID-19 as well, what is stopping the Modi government from treating it as a natural disaster?
2. What support has the government provided to the families of the deceased so far and why is the government reluctant to provide compensation to the families of the deceased?
3. The excessive Excise duty on petrol and diesel that the government collects is the public money. If the government can't spend 10% (Rs 40,000 Crore) of it on the families of the deceased, what is the use of this money?

Shri Rahul Gandhi ji has time and again proposed that the government set-up a COVID Compensation fund and provide a compensation of Rs 10 Lakh to families of the deceased. This is not just a constitutional obligation but a moral one too. The Congress party demands that the government include COVID-19 like other natural disasters and provide compensation of Rs 10 lakhs to the families of the deceased. It is our debt of gratitude to the families of the deceased. It is an insult to the frontline workers who have laid down their lives in fighting at the forefront. A government that can't provide Rs 10 Lakh to the families of the deceased has no right to rule.

Annexure 1: US Disaster Declaration

Congressional Research Service
Informing the legislative debate since 1914

Federal Emergency and Major Disaster Declarations for the COVID-19 Pandemic

SUMMARY

In early 2020, the federal government began to express concerns over the global spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In the months following, President Donald J. Trump and other executive officials issued dozens of emergency and major disaster declarations under at least four different statutory authorities:

1. On January 31, 2020, then-Secretary of Health and Human Services (HHS) Alex Azar declared a Public Health Emergency under the Public Health Service Act (PHSA) for the COVID-19 pandemic;
2. On March 13, 2020, President Trump issued Proclamation 9994 under the National Emergencies Act (NEA);
3. On the same day, President Trump also declared a nationwide emergency under the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (Stafford Act) for the pandemic. President Trump later approved major disaster declaration requests under the Stafford Act for all 50 states, five territories, the District of Columbia, and the Seminole Tribe of Florida. President Joseph R. Biden Jr. would later go on to approve major disaster declaration requests from the Navajo Nation and the Poarch Band of Creek Indians; and
4. On March 16, 2020, then-Administrator of the U.S. Small Business Administration (SBA) Jovita Carranza began issuing disaster declarations under the Small Business Act, authorizing Economic Injury Disaster Loans to businesses suffering economic injury as a result of the pandemic.

These declarations remain in effect as of June 4, 2021.

This report summarizes the provisions, durations, and interrelationships of these four types of federal declarations issued for the COVID-19 pandemic. These declarations provide distinct authorities and forms of assistance deployed in the federal pandemic response.

This report focuses on authorities and assistance activated specifically by the federal declarations for the COVID-19 pandemic. It does not provide in-depth discussions of the statutory frameworks behind these emergency authorities, nor is it a catalogue of federal statutes, regulations, or policies contingent upon these types of declarations. Rather, it focuses on the key emergency declarations in effect for the COVID-19 pandemic response. Under these declarations, the Trump and Biden Administrations have accessed enhanced executive authorities, furnished assistance of many types, and taken other administrative actions to facilitate response and recovery. Many of these contingent authorities and actions will lapse when the declarations themselves lapse or are terminated.

R46809

June 4, 2021

Erica A. Lee, Coordinator
Analyst in Emergency Management and Disaster Recovery

Sarah A. Lister, Coordinator
Specialist in Public Health and Epidemiology

L. Elaine Halchin
Specialist in American National Government

Bruce R. Lindsay
Specialist in American National Government

Elizabeth M. Webster
Analyst in Emergency Management and Disaster Recovery

Hassan Z. Sheikh
Analyst in Public Health Emergency Management

Jared C. Nagel
Senior Research Librarian

workers, but also other workers who may have been drafted for work in relief or response to COVID-19. This insurance cover has been made available from the inception of the pandemic and it provides a sum more than 12 times larger than the sum being sought in the writ petition.

51. It is respectfully submitted that as regards the prayer for *ex-gratia* to kin of all persons, who have died due to COVID, while all casualties are a matter of deep regret and sadness and a colossal loss to the family and the nation, it is imperative to appreciate the current approach in the light of a few important considerations. This epidemic is a disaster, unlike any other that the country (and the world) has experienced in a long time. Its extraordinary spread and impact, requires an approach different from the one that is applied to a natural disaster, which has limited and defined dimensions in terms of geography, population, and overall losses. The pandemic is still not over in the country as also the world and it is extremely difficult to predict with accuracy, it's further trajectory, mutations and waves. It requires rapidly scaled-up health and non-health efforts for a long period of time which will cost the nation lakhs of crores. There is a need to focus simultaneously on prevention, preparedness, mitigation, and recovery, which calls for a different order of mobilization of both financial and technical resources. Due to its scale and impact, it

would not be appropriate to apply the scheme of assistance, eligible for natural disasters, to the epidemic.

52. The pandemic has caused more than 3,85,000 deaths, a number which is likely to increase further. It exceeds the number of deaths in any other natural disaster in the past, in the country. These deaths have affected families from all classes - the rich and poor, professionals and informal workers, and trader and farmers. The Government is fully conscious of the need to provide them the necessary help and support. However, it is not correct to state that such support could be provided only through *ex-gratia* assistance for those who have died. In the current context of the pandemic, it would be a rather pedantic and narrow approach. A broader approach, which involves health interventions, social protection, and economic recovery for the affected communities, would be a more prudent, responsible, and sustainable approach. Globally, the Governments in other countries too have followed this approach, and have announced interventions that provide fiscal stimulus. The Government of India has followed a similar approach.

53. It is further submitted that, in the case of various disasters, for which such *ex-gratia* is provided under SDRF norms, the disaster is of a short and finite duration, occurring and ending quickly. Covid-19, on the other hand,

Therefore, if an *ex-gratia* of Rs.4 lakhs is given for every person, who loses life due to COVID-19, the entire amount of SDRF may possibly be spent on this item alone, and indeed the total expenditure may go up further. In this regard it is submitted that, Public Health is a State subject under the 7th Schedule of the Constitution. If the entire SDRF funds get consumed on *ex-gratia* for COVID-19 victims, the States may not have sufficient funds for organizing Covid-19 response, for provision of various essential medical and other supplies, or to take care of other disasters like cyclones, floods, etc. Hence, the prayer of the petitioner for payment of *ex-gratia* to all deceased persons due to COVID-19, is beyond the fiscal affordability of the State Governments. Already the finances of State Governments and the Central Government are under severe strain, due to the reduction in tax revenues and increase in health expenses on account of the pandemic. Thus, utilisation of scarce resources for giving *ex-gratia*, may have unfortunate consequences of affecting the pandemic response and health expenditure in other aspects and hence cause more damage than good. It is an unfortunate but important fact that the resources of the Governments have limits and any additional burden through *ex-gratia* will reduce the funds available for other health and welfare schemes.

श्री अमन पंवार ने कहा कि सबसे पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसका सेक्शन 2 (D) है, वो डिजास्टर को डिफाइन करता है। और जो अभी यथार्थ सेक्शन 2 (D) है, उसमें हर एक टाइप की इमरजेंसी, आपदा, कैलेमिटी या कोविड जैसी सिचुएशन जो है, उसके अंतर्गत उसकी परिभाषा में आती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 14 मार्च, 2020 को खुद गृह मंत्रालय ने कोविड 19 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डिजास्टर की डेफिनेशन में नोटिफाई किया था। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये 14 मार्च, 2020 को जब ये आपदा शुरु हुई, उस समय पर गृह मंत्रालय ने इसको ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है, तो सरकार कहती है कि अगर हमने इसको नोटिफाई भी किया हुआ है, तो इसको कंपनसेशन के रुप में आप नहीं देख सकते। हालांकि बात ये है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वो बिल्कुल क्लियरली ये बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी डिजास्टर में जो चीजें नोटिफाई हुई हैं, जैसे वो भूकंप है, चाहे वो साइक्लोन है या कोविड 19 है, जो 14 मार्च, 2020 को ऑलरेडी नोटिफाई है, अगर किसी व्यक्ति की इन डिजास्टर के कारण मृत्यु हो जाती है, तो as per the existing policy उसको 4 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलेगा।

कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि इस कंपनसेशन को बढ़ाकर आप 10 लाख रुपए करिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप सेक्शन 2 (D) की डेफिनेशन बदलना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक पार्लिय़ामेंट में अमेंडमेंट लाकर हो सकता है। और हम देखना चाहेंगे कि क्या सरकार पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर आना चाहेगी। 2005 का जो डिजास्टर मैनजमेंट एक्ट है, उसमें आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए और देखते हैं आपके जो एमपी हैं, जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो ये बात कहेंगे, इस बात पर डिबेट करना चाहेंगे कि सेक्शन 2 (D) में आप अमेंडमेंट लेकर आइए, ताकी कोविड़ 19 के जो विक्टिम हैं, उनको कंपनसेशन की डेफिनेशन से बाहर किया जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा।

दूसरी तरफ सरकार क्या कहती है अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के कि ये पॉलिसी डिसीजन है। ये हमने डिसाइड कर लिया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी ना करे, ये ज्यूडिशरी का काम नहीं। तो एक तरह से डराने का, धमकाने का काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट को सरकार। ये बात सरकार समझ ले कि ये देश है, ये व्हिम्स और फैंसीज पर नहीं चलता, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है और जो कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो यूपीए के दौरान हम लेकर आए थे, उस एक्ट में ये प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है और डिजास्टर की जो डेफिनेशन है, 2005 के एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट है। उसके अंदर कोविड और कोविड विक्टिम जो हैं, उनके लिए कंपनसेशन का प्रावधान है। मोदी जी 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से अगर नाखुश हैं, उनको ये डेफिनेशन समझ नहीं आती, तो लीगली उनको 2005 के एक्ट में अमेंडमेंट

करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप अपनी कन्नी नहीं काट सकते, आप लोगों को कंपनसेशन देने से नहीं भाग सकते।

प्रो. गौरव वल्लभ ने पुन: कहा कि शुरुआत होती है कि हम पहले जान बचाएंगे, फिर जहान बचाएंगे। फिर बीच में बोला गया कि अब जान तो बच गई, अब जहान बचाएंगे। फिर अचानक से चुनाव में जिस तरह की घटनाएं हुई पिछले दो–तीन महीनों में, ना तो हम जीडीपी को माइनस 7.73 प्रतिशत होने से रोक पाए, ना हम लोगों की जान बचाने में कामयाब हो पाए। We lost at the both fronts, both lives and livelihood, why- because government was not clear कभी बोले जान, कभी बोले जहान, ऐसे देश में लाइफ और लाइवलीहुड इंटर डिपेंडेंट हैं each other पर, एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है, इसलिए हमारी जो मांग है कि आज के समय में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों के परिवारों को आर्थिक संबल देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी तो है ही जैसा मेरे साथी ने बताया, पर नैतिक जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी का वहन करने में पूरा बजट नहीं, पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी की लूट का मात्र 10 प्रतिशत चाहिए, जिससे कि 10 लाख रुपए हर मृतक के परिवार के आश्रितों को दे दिया जाए और ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फेल हुए लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि हमने उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दी, हमने पर्याप्त दवाई नहीं दी, हमने पर्याप्त आईसीयू बेड सपोर्ट नहीं दिया। हमने पर्याप्त इंजेक्शन नहीं दिए, हम समय पर उनको एंबुलेंस नहीं पहुंचा पाए। इस कारण से ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये लीगल लैंग्वेज से आईडेंटिफाइड आपदा, अन आईडेंटिफाइड आपदा। अब आप ये बताइए कि आपदा का मतलब क्या होता है – आपदा, क्या कोई अर्थ क्वेक कहकर आता है कि मैं कल सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर आऊंगा, ऐसा होता है क्या? फ्लड बोलकर आती है क्या कि मैं 20 दिन बात रात के 11 बजकर 15 मिनट पर आऊंगी। ये किस तरह का गवर्नेंस मॉडल सरकार देश के लोगों को देना चाहती है और जो सरकार इस समय भी लोगों की भावनाओं को ना समझते हुए उनको राजनीति में शब्दों के जाल में उलझाना चाहती है, उस सरकार को एक क्षण भी शासन में रहने का अधिकार नहीं।

एक प्रश्न पर कि जो तैयारियों की घोषणा सरकार ने की है दोनों ही फ्रंट पर, हैल्थ और इकॉनमिक फ्रंट पर उसको कांग्रेस कैसे देखती है, प्रो. गौरव वल्लभ ने कहा कि माननीय वित्तमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी के अनुवादक जी ने, दोनों ने प्रेस वार्ता की। मैंने भी पूरी प्रेस वार्ता पूरी गंभीरता से सुनी ये सोचकर कि इस प्रेस वार्ता से जो निरंतर गिरती हुई इकॉनमी है, उसको कोई संबल मिलेगा। मैं बहुत ही जनरलिस्टिक 3-4 बातें आप सबके सामने रखूँगा कि इकॉनमी की समस्या क्या है। आज इकॉनमी की अगर मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं कि इकॉनमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, लो जीडीपी, हाई इंफ्लेशन, लो डिमांड, हाई अनएम्पलॉयमेंट, बस इन चार मुद्दों पर माननीय वित्तमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। ये जो बात हिंदुस्तान की हर गृहणी को, हर युवा को, हर मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को, हर निम्न आय वर्गीय परिवार को समझ में आ जाती है, वो माननीय वित्तमंत्री जी को क्यों नहीं समझ में आती, उनके अनुवादक को नहीं

आती, कोई बात नहीं, पर माननीय वित्तमंत्री जी तो समझे इस चीज को कि लो डिमांड को वापस क्रिएट करने के लिए इकॉनमी को हाई डिमांड पर लाने के लिए आपने क्या किया? जो बेरोजगारी की दर 12 प्रतिशत है, उसको नीचे लाने के लिए आपने क्या किया? जो इंफ्लेशन आज 6.3 प्रतिशत है, जो पेट्रोल-डीजल का इंफ्लेशन 60 प्रतिशत है, मई 2021 का आंकड़ा दे रहा हूँ, उस पर जवाब आपने एक घंटा, 10 मिनट की प्रेस वार्ता में आपने उसके लिए क्या बात की- आपने क्या बात की कि ईसीएलजीएस स्कीम के तहत 1,10,000 करोड़ का ऋण देंगी। माननीय वित्तमंत्री जी, ये लोन की खुराक के मॉडल का रिजल्ट आ गया। जब दुनिया की सारी इकॉनमीज रिवाइव कर रही थी, रिवाइव होना चालू हो गई, हम नहीं कर पाए क्योंकि आपने जो पहला पैकेज था पिछले साल उसमें भी लोन की खुराक की बात की। लोगों को लोन के खुराक की नहीं, आपके हैंड़ होल्डिंग की, आपके हाथ पकड़ने की जरुरत थी। लोगों को जरुरत थी कि आप किस तरह लोगों के खाते में सीधा पैसा डालो ताकि नई मांग का सृजन हो, नए रोजगार का सृजन हो, नए निवेश का सृजन हो, लोगों को ये आकांक्षा थी, अर्थशास्त्रियों को ये आकांक्षा थी।

माननीय वित्तमंत्री जी, जो आपने पहले गलती की, 20 लाख करोड़ की बात की और मात्र 2 लाख करोड़ का डायरेक्ट फिस्कल सपोर्ट दिया, बाकी 17-18 लाख करोड़ रुपया लोन की खुराक और लिक्विडिटी मेजर्स थी और आपने देश के ऊपर तो ईसीएलजीएस स्कीम पहले एमएसएमई के लिए चल रही है, उसका ब्यौरा दिया माननीय वित्तमंत्री जी? जो आपने सवाल पूछा, एक्सपोर्ट क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम जो चल रही है, उसमें हमने क्या पाया, हमने क्या पाया कि आज 80 प्रतिशत एमएसएमई बंद हो रही हैं। हमने क्या पाया की एमएसएमई सेक्टर ब्लीड कर रही है, क्यों आपको ये बात समझ में नहीं आई माननीय वित्तमंत्री जी और आपको नहीं आई तो ठीक है, आपके एडवाइजर कौन हैं, जो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि वापस लोन की खुराक दो इकॉनमी में। इकॉनमी को 4 चीजों का उत्तर चाहिए, और मैं वापस दोहराता हूँ।

What is the answer for the consistent decline in GDP? How you are going to revive that? As per the RBI's statement, only in the month of April and May, 2 lakh crores of GDP, as per RBI's estimate was lost?

Second question that what is the answer of Hon'ble Finance Minister that today the unemployment rate is 12%, in 2012 it was 2%, how we are going to bring down this unemployment rate? How we are going to create new employment? What is the answer in this regard, answer is- no. There is no concrete plan.

The third thing, which I would like to ask, that there is a consistent decline in the demand in the economy, what you had done to revive the demand in the economy? People are losing jobs, there are salary cuts, and government is not transferring the dearness allowance to its employees, the people are in crisis.

So, I was discussing with you that what are the 4 issues, 4 biggest challenges in front of economy- low demand, low GDP, high unemployment and high inflation. Had the Finance Minister given any concrete suggestion to address any of the 4 of these things? She again tried to give a treatment of

loan to an ever declining GDP in the economy, that is what, I was precisely asking.

हमारी इकॉनमी को रिवाइव करने का एक ही तरीका है, कि नई मांग का सृजन, इकॉनमी में करना पड़ेगा। नई मांग का सृजन करने के लिए हमारा कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारी इकॉनमी, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी नहीं है, कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है। लगभग 55 प्रतिशत जीडीपी का कंजम्पशन से आता है और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। जो डाइंग एमएसएमई हैं, जो बंद हुई एमएसएमई हैं, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, उनको जबरदस्ती लोन की खुराक नहीं दी जा सकती है।

That is what I would like to ask Hon'ble Finance Minister that in your last year's package also, as per IMF and various other agencies, the truth of 20 lakh crore is something around 2 lakh crores, the fiscal stimulus is only Rs 2 lakh crores. So, today also what is the direct support, what is the additional expenditure which Government of India is going to make to revive the economy? What is the additional money Government of India is going to transfer in the hands of the people, who are losing the jobs, who are having massive salary cuts? Who are not getting salary for last 4-5 months, what you are doing for that? Without taking care of that, without taking care of ever falling demand, without taking care of reviving the new demand in the economy, you can't come out of this vicious circle and what is this vicious circle, low GDP, low demand, high unemployment, high inflation. इस चक्र से बाहर आने के लिए नई मांग का सृजन करना पड़ेगा और नई मांग के सृजन के लिए लोगों को पैसा देना पड़ेगा ताकि वो खर्चा करें, स्पैंड करें, कंज्यूम करें। ताकि इकॉनमी वापस पटरी पर आए और रोटेट करना चालू कर दे।

Unfortunately, माननीय वित्तमंत्री जी को ये बात समझ में नहीं आती। दुर्भाग्य से उनके सलाहकारों को ये बात नहीं समझ में आती। दुर्भाग्य से आज फिर उन्होंने वही गलती की, जो 2020 में की और 2020 में जो स्टिमुलस का नाम था, जो 20 लाख करोड़ की बात की गई थी As per experts, as per IMF, as per various other investment banks and agencies the truth of Rs. 20 lakh crore, the financial support of Rs. 20 lakh crore, the fiscal stimulus of Rs 20 lakh crore is only Rs 2 lakh crores.

On another question about Pradhan Mantri Rojgar Yojana expansion and promising doubling of farmer's income in Finance Minister's press conference, Prof Vallabh said- EPFO scheme, which Finance Minister had mentioned is already in existence. Had we received benefit out of that? Despite of this scheme our unemployment rate is 12%, which is 6 times of what was the unemployment rate in the year 2012. So, EPFO scheme is not giving the benefit, what is that scheme that Government is going to contribute in the EPFO or employers and employees contribution, but, when there is no job, government is going to contribute for whom? You have to create the jobs and jobs can be created, when there is demand in the economy. For example, I am a manufacturer of this pen, I will manufacture

this pen, when there is demand in the economy, but, demand will be there when people will have money to buy this pen, this is the simple economics, which Hon'ble Finance Minister is neither ready to listen nor she understand these things. Again she is telling- EPFO scheme, I am extending. What is the benefit we had received in last one year, can she give a white paper on that? Again, she is telling 1.1 lakh crore of ECLGS scheme. What is the benefit of ECLGS, can she give a white paper on that? How many MSMEs got the benefit of ECLGS? How many MSMEs were closed down, is she aware, is her Ministry aware of this particular data? So, coming to a job scheme, the fundamental truth is that, that new jobs can be created in the economy when the unutilized capacity of the manufacturing sector will be utilized and when there is new demand in the economy and when there will be a new demand in the economy- when the people will start the consumption because, our's is a consumption led economy, our's is not a export, import led economy, so this is the answer to your first question.

Regarding the doubling of the farmers income, in last 7 months, 5+2=7 months, our Annadatas are there at the borders of Delhi. Government is not having time, neither to go there, nor to call them for the discussion. What is the government's reaction,- *"ye kisaan nahin hain, ye khalistani hain, ye thalue hain, ye Canada ke agent hain, ye Pakistan ke agent hain, ye atankwadi hain, ye rajnitik log hain"*. Are they political people? In the 43^{o}C summer and in the 0^{o}C winters, they were on the roads at the borders of national capital and government is reluctant to talk to them, government is saying *"Hum kuch bhi ho jaye, teen bilon par baat nahin karenge"*. They are asking that make MSP as a legal right, no, we are not going to make, and we have said this at the floor of the house. At the floor of the house, you had also said that we are going to create hundred smart cities, and on the floor of the house, you had told to the country that 2 crore jobs will be created every year. On the floor of house you mentioned that the 'Ganga Maiya' is going to be completely cleaned by a particular date, on the floor of the house you had mentioned that Make in India is going to contribute or increase the contribution of manufacturing sector in the GDP of our economy, what happened to those promises?

Farmers are saying that give us the legal right, MSP should be our legal right, why government can't give that? When Hon'ble Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, he himself used to demand that the MSP should be legally enforceable, why he can't follow, what he submitted to the government at that time, when he was the Chief Minister of the Gujarat. जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि एमएसपी लीगली इन्फोर्सिबल होनी चाहिए, वो अपनी ही बात नहीं मान रहे और Hon'ble Finance Minister is talking about doubling of farmers' income.

I am just asking two question on behalf of the every citizen of our country:-

Is 5 trillion dollar economy is still 2024-25, is our deadline or we had extended that, number one and you had promised that by 2021-2022, the farmers income will be doubled. What we had received, what is the current status, had we increased by 5%,10%,15%,19%, the entire country wants to know about this.

And the last but not the least, that come out of your arrogance, अपने अभिमान से बाहर आओ, अन्नदाताओं से हाथ जोड़कर उनकी बात सुनो, उनकी बात समझो and make the MSP as a legal right that is not something which they are asking that give us favour that is their right. When you, yourself used to say, that MSP should be given as a legal right, why it is not given till now? When you, yourself used to say, that comprehensive cost plus 50 percent should be equal to the MSP, why by giving affidavit in the Supreme Court, you say, the एसएसपी कॉस्ट प्लस 50 प्रतिशत सरकार नहीं दे सकती।

जब आप 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ले रहे हो, न आप एमएसपी देते हो, न आप मृतक परिवार के आश्रितों को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देते हो और किसान अगर अपनी मांग करते हैं तो आप कह देते हो किसान आतंकवादी है, किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी हैं, ठलुए है, केनेडा के एजेंट हैं। ये भाषा है, माननीय मंत्रियों की, माननीय विधायकों की, माननीय सांसदों की, हमारे अन्नदाताओं के लिए। जब 10 लाख रुपए की बात हम करते हैं कि हर, जो व्यक्ति ने कोविड में अपनी जान गंवाई उसके परिवार को 10 लाख रुपए का सम्मान दिया जाए तो आप कहते हो कि दो तरह के डिजास्टर होते हैं, आईडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड। हम सिर्फ सहायता राशि देते हैं, जो डिजास्टर आइडेंटिफाइड होते हैं, जो अनआइडेंटिफाइड होते हैं, उसमें कोई सहायता राशि नहीं है। Is this a government which is elected by the people of our country? लोगों से चुनी हुई सरकार से क्या कोई ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता है? हमारे देश के लोगों ने आपको चुना है, और आप देश के लोगों से जो पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी के रूप में पैसा ले रहे हो, लूट रहे हो, वो पैसा आप लोगों को वापस नहीं दे सकते हो, उन आश्रितों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई। So, this is my two precise answers to your specific two questions on Madam FM's press conference.

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC